

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र

प्रलिस के ललल:

सरवोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), सीलबंद कवर न्यायशास्त्र ।

मेन्स के ललल:

न्यायपालका, भारतीय संवधान, मौलक अधकार, मुहरबंद कवर न्यायशास्त्र ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में बहलर सरकार के खललफ एक आपराधकल अपील पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक वकील को अदालत में 'सीलबंद कवर रर्पोरट' प्रस्तुत करने के ललल कहा है ।

- बीते कुछ दनलौं में वभलनलन न्यायालयौं द्वारा 'सीलबंद कवर न्यायशास्त्र' का प्रलय: इस्तेमाल कलल गया है, उदाहरण के ललल [राफेल फाइटर जेट समझौता \(2018\)](#), बीसीसीआई सुधार मामला, [भीमा कोरेगाँव मामला \(2018\)](#) आदल

'सीलबंद कवर न्यायशास्त्र' क्या है?

- यह [सरवोच्च न्यायालय](#) और कभी-कभी नचलली अदालतौं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रथा है, जसके तहत सरकारी एजेंसललौं से 'सीलबंद लफलाफौं' में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार कलल जाता है कल केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं ।
- यदयप कौई वशलषलट कानून 'सीलबंद कवर' के सदलधांत को परभलषतल नहीं करता है, सरवोच्च न्यायालय इसे सरवोच्च न्यायालय के नललमौं के आदेश XIII के नललम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधनललम की धारा 123 से उपयोग करने की शकर्ता प्राप्त करता है ।
 - **सरवोच्च न्यायालय के आदेश XIII के नललम 7:**
 - नललम के अनुसार, यदल मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ सूचनाओं को सीलबंद लफलाफे में रखने का नरदलेश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकर्ता का मानते हैं, तो कसलसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामगरी तक पहुँच की अनुमतल नहीं दी जाएगी, सवलल इसके कल मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दे कल वलपलरलत पक्ष को इसे एक्सेस करने की अनुमतल दी जाए ।
 - इसमें यह भी उललेख कलल गया है कल सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदल इसके प्रकाशन को जनता के हतल में नहीं माना जाता है ।
 - **वर्ष 1872 के भारतीय साक्ष्य अधनललम की धारा 123:**
 - इस अधनललम के तहत राज्य के मामलौं से संबंधतल आधकारकल अप्रकाशतल दस्तावेजौं की रक्षा की जाती है और एक सरकारी अधकारल को ऐसे दस्तावेजौं का खुलासा करने के ललल मजबूर नहीं कलल जा सकता है ।
 - अन्य उदाहरण जहाँ गोपनीयता या वशलवास के तहत जानकारी मांगी जा सकती है, इसका प्रकाशन जाँच में बाधा डालता है जैसे- **वलरलण (Details)** जो पुलसल केस डायरी का हसलसा है ।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र से संबंधतल मुददे:

- **पारदर्शतल और जवाबदेही के सदलधांतौं के खललफ:**
 - यह भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शतल और जवाबदेही के सदलधांतौं के अनुकूल नहीं है, क्यौंकल यह एक खुली अदालत के वचलर के वरुदध है, जहाँ नरलणय सार्वजनकल जाँच के अधलन हो सकते हैं ।
 - न्याय-नरलणयन की कसलसी भी प्रकरलल में वशलष रूप से जसलमें **मौलक अधकार** शामिल हैं, इसके ववलदौं से संबंधतल साक्ष्य" **दोनौं पक्षौं के साथ साझा कलल जाने चाहलल** ।"
- **दलीलौं का दायरा कम करना:**
 - अदालत के फैसलौं में स्वेच्छाचलरतल के दायरे को बढ़ाना, क्यौंकल न्यायाधीशौं को अपने फैसलौं के ललल तरक देना होता है, जो तब तक नहीं

किया जा सकता, जब तक की वे गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी पर आधारित न हों।

- आगे इसका वरिष्ठ किया जाता है कि जब कैमरे के समक्ष सुनवाई जैसे मौजूदा प्रावधान पहले से ही संवेदनशील जानकारी को प्रयाप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं तो क्या राज्य को गोपनीयता के साथ जानकारी प्रस्तुत करने का ऐसा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिये।

■ नषिपक्ष परीक्षण और न्याय-नरिणयन में बाधा:

- यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोपी पक्षों को ऐसे दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान नहीं करना उनके नषिपक्ष परीक्षण और न्याय-नरिणयन के मार्ग में बाधा डालता है।

■ मनमानी प्रकृति:

- सीलबंद कवर **अलग-अलग न्यायाधीशों पर नरिभर** होते हैं जो सामान्य अभ्यास के बजाय किसी विशेष मामले में एक बट्टि की पुष्टि करना चाहते हैं। यह अभ्यास को तदर्थ और मनमाना बनाता है।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- **मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अहरोन बराक द्वारा प्रस्तावित अनुपातकितता के परीक्षण** को अपनाया, जिसके अनुसार "संवैधानिक अधिकार की एक सीमा संवैधानिक रूप से अनुमेय होगी यदि:
 - इसे एक उचित उद्देश्य के लिये नामित किया गया है।
 - इस तरह की सीमा को लागू करने के लिये किये गए उपाय तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हों।
 - किये गए उपाय इसलिये आवश्यक हैं क्योंकि ऐसा कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं है जो समान रूप से उसी उद्देश्य को कम सीमा के साथ प्राप्त कर सके।
 - उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्त्व और संवैधानिक अधिकार की सीमा नरिधारित करने के सामाजिक महत्त्व के बीच एक उचित संबंध ('proportionality stricto sensu' or 'balancing') हो।
- **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** मामले में इस बात को दोहराया गया था।
- पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में 2019 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेजों का खुलासा करना संवैधानिक रूप से अनविर्य है, भले ही जाँच जारी हो क्योंकि दस्तावेजों से मामले की जाँच में सफलता मिल सकती है।
- वर्ष 2019 में INX मीडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय (ED) द्वारा सीलबंद लफिफे में जमा किये गए दस्तावेजों के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लिये दलिली उच्च न्यायालय की आलोचना की थी।

आगे की राह

- **न्यायिक समीक्षा** की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती है।
- कार्यपालिका को अपने **कार्यों का दृढ़ता से जवाब देना चाहिये** - विशेष रूप से तब जब **मौलिक अधिकारों**, जैसे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति में कटौती की जाती है। भारत का संविधान कार्यपालिका को ऐसे **अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मनमाने आदेश पारित करने की छूट नहीं** देता है।
- एक न्यायालय जो किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के दौरान मूकदर्शक बना रहता है, वह अपरिष्कृत रूप से लोकतांत्रिक वनिश को दर्शाता है।
- जब किसी कार्रवाई पर मौलिक अधिकारों को कम करने का आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय अनुपातकितता की दृष्टि से कार्रवाई की वैधता की जाँच करने के लिये बाध्य होता है।

स्रोत: द हट्टि